ताल-बेताला

शशिकांत गुप्ते,
मोबाइल नं.
78984-88217

उजाला होगा मिटेगा अंधेरा

आस्था,अस्मिता,नैतिकता
नीति,सिद्धांत,संवेदनाएं,और शुद्ध भावनाएं,इन सारे मानवीय गुणों को सत्ता,पूंजी,युक्त भ्रष्टाचार ने लील लिए।

इसीलिए एक ओर शुचिता की दुहाई देना और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों से गलबहियां कर उनकी ताजपोशी करना। देश के 22 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी निष्ठुर बने रहना।

शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही ने 25 युवाओं को परलोक पहुंचा दिया।

लोक पर तंत्र को हावी कर लोकतंत्र को कमजोर करने की साज़िश रचना और स्वयं को महामानव घोषित करना। यह

तानाशाह प्रवृत्ति है। तानाशाही प्रवृत्ति को आत्मसात करने वालें इतिहास को भूल जातें हैं।

जो भी तानाशाह होता है,वह कायर होता है,अपनी कायरता को छिपाने के लिए धार्मिक आवरण ओढ़ लेता है।

तानाशाह का सबसे बड़ा अवगुण अहंकार होता है।

अपने अहंकार को जायज ठहराने के लिए अपने इर्दगिर्द चाटुकारों,और

अंधभक्तों की फ़ौज खड़ी कर रखता है। अहंकार व्यक्ति को हठ धर्मी बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी हठ धर्मिता के कारण अपने मातहत आयोग्य लोगों को ही रखता है। वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री और भी कुछ मंत्री है जिन्हें महामानव ने अपने अड़ियल रुख के कारण मंत्री बनाए रखा है।

अहंकार का नतीजा क्या होता है,यह निम्न कहावत में स्पष्ट होता है।

अहंकार में तीनों गए, धन,वैभव और वंश
ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव, कंस

वास्तव में अहंकार एक मानसिक रोग है,अहंकार वह व्यक्ति ही करता है जिसका आत्मबल कमजोर होता है। जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में अक्षम होता है।

ऐसे व्यक्ति नित नए वादें करते रहतें हैं। अहंकारी लोगों का वादें करने का तरीका शायरा शगुफ्ता यास्मीन गज़ल के द्वारा रचित निम्न शेर में स्पष्ट होता है।

ज़हर का जाम ही पिलाऐंगे।
लोग मीठी सी गुफ्तगू कर के।

विश्व के क्रूर कुख्यात तानाशाहों की फेहरिस्त है हलाकु,हिटलर,मुसोलिनी, स्टालिन और जारा आदि के अंत का इतिहास भी गवाह है।

यह भी सत्य है कि तानाशाहों के विरुद्ध लड़ने वालों का इतिहास,इतिहास के पन्नो पर स्वर्ण अक्षरों में लिपि बद्ध है।

अहिंसक लोग निर्भीक होते हैं,और इनका जुनून कैसा होता है यह शायरा हिना रिज्वी के द्वारा रचित निम्न अशआर पढ़ने पर ज्ञात होता है।

आंधियों को ये गुमां है कि बुझा देंगी चराग़
और चराग़ों की ये ज़िद है कि उजाला हो जाए
टूट सकता है किसी पल भी समुंदर का गुरूर
मुंह अगर मोड़ ले दरिया तो ये प्यासा हो जाए

असल में अहंकार मानव की मनुष्यता को खत्म कर देता है। यह वास्तविकता निम्न शेर में बयां होती है।

कौन कहता है कि हर शख्स फ़रिश्ता हो जाए
आदमी थोड़ा इंसान के जैसा हो जाए
आदमी होगा तो ही इंसान बनेगा,हैवान क्या उम्मीद करें?
इतना ही काफी है।

प्रदेश के सभी बांधों पर 24 घंटे निगरानी

कारम और राजा बांध हादसों से सबक ; जल संसाधन विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश, इंजीनियर रहेंगे हाई अलर्ट पर

भोपाल । मध्यप्रदेश में मानसून के दौरान बांधों की सुरक्षा को लेकर जल संसाधन विभाग ने इस बार अभूतपूर्व सतर्कता बरतने का फैसला किया है।

वर्ष 2022 में धार जिले के कारम डैम टूटने और पिछले वर्ष मैहर के राजा बांध में आई तकनीकी समस्या से सबक लेते हुए विभाग ने सभी इंजीनियरों को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि बारिश के पूरे सीजन में बांधों के संचालन और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग के अनुसार, मानसून के दौरान जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ता और बदलता है। ऐसे में छोटी-सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए सभी फील्ड इंजीनियरों को बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और हर स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक इंजीनियर केवल कार्यालय से निगरानी नहीं करेंगे, बल्कि स्वयं मौके पर पहुंचकर बांधों की दीवारों, गेटों, स्पिलवे (जल निकासी मार्ग) और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं का नियमित निरीक्षण करेंगे। विशेष रूप से पुराने बांधों और उन परियोजनाओं पर अतिरिक्त निगरानी रखने को कहा गया है, जहां पहले किसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने आ चुकी है। बांधों के आसपास जमा मलबा, झाड़ियां और अन्य अवरोध हटाकर जल निकासी को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं दरार, रिसाव, मिट्टी का कटाव या किसी भी प्रकार की संरचनात्मक कमजोरी दिखाई देती है तो उसकी तत्काल सूचना मुख्यालय को देकर मरम्मत कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा।

पानी छोडऩे में नहीं होगी जल्दबाजी

जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि जलाशयों से पानी की निकासी पूरी तरह वैज्ञानिक मानकों और बांध की निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही की जाए। अचानक भारी बारिश की स्थिति में अलर्ट सिस्टम को तत्काल सक्रिय करना होगा, ताकि नीचे बसे गांवों और प्रशासन को समय रहते सूचना मिल सके। विभाग चाहता है कि जल प्रबंधन में किसी प्रकार की जल्दबाजी या मानवीय भूल से बचा जाए।

हर बांध के लिए तैयार किया गया इमरजेंसी एक्शन प्लान

इस वर्ष विभाग ने प्रदेश के प्रत्येक बांध के लिए अलग-अलग इमरजेंसी एक्शन प्लान तैयार किया है। इस योजना में शामिल हैं- संभावित खतरे की स्थिति में आसपास के गांवों को समय पर चेतावनी देना। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था। बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मशीनरी और संसाधनों की अग्रिम तैयारी। जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय। साथ ही, 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर तय कर दी गई है, ताकि हर समय प्रशिक्षित अधिकारी मौके पर उपलब्ध रहें।

अधूरे मरम्मत कार्य तत्काल पूरे करने के निर्देश

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन बांधों में मरम्मत, पेंटिंग या अन्य रखरखाव संबंधी कार्य अभी अधूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही या समय पर कार्रवाई न करने के कारण दुर्घटना होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अब एप से होगी लाइव मॉनिटरिंग

इस बार जल संसाधन विभाग ने तकनीक का भी व्यापक उपयोग शुरू किया है। सभी इंजीनियरों को रोजाना बांधों का जलस्तर, वर्षा की मात्रा और पानी की निकासी से संबंधित जानकारी डिजिटल एप और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से सीधे भोपाल मुख्यालय भेजनी होगी। इससे प्रदेश स्तर पर हर बांध की स्थिति की रियल टाइम निगरानी संभव होगी और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निर्णय लिए जा सकेंगे।

अब कॉलेज सुधारेंगे आंगनबाडियों की हालत!

महिला बाल विकास ने उच्च शिक्षा विभाग को लिखा पत्र...

भोपाल । मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के कामकाज और प्रशासनिक क्षमता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग प्रदेश के नौनिहालों और आंगनबाडियों की जिम्मेदारी संभालने में पूरी तरह हांफता नजर आ रहा है।

अपनी इस नाकामी या व्यवस्थागत लाचारी को छिपाने और बोझ को कम करने के लिए विभाग ने अब एक नया रास्ता निकाला है। प्रदेश की आंगनबाडियों को संभालने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आगे लाया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग ने बाकायदा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस मामले में सीधी मदद मांगी है। यह पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक और उसकी रिपोर्ट के बाद सतह पर आया है। मुख्य सचिवों की पांचवीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग को आंगनबाडियों की हालत सुधारने के कड़े निर्देश मिले थे। इसी कॉन्फ्रेंस की 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' और बाल अवस्था देखभाल शिक्षा के लक्ष्यों का हवाला देते हुए महिला बाल विकास विभाग ने यह पत्र लिखा है। विभाग का तर्क है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सामुदायिक स्वामित्व और जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज गोद लेंगी आंगनबाडियां!

महिला बाल विकास विभाग के इस सरेंडरनुमा पत्र के बाद उच्च शिक्षा विभाग में भी खलबली मच गई है। पत्र मिलते ही उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और कॉलेजों को पत्र जारी कर दिया है। इस नए आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के सभी सरकारी-निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने-अपने क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों को गोद ले सकेंगे और उनकी पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे।

मप्र पुलिस में बड़े बदलाव की आहट

डीजीपी की दौड़ तेज, तीन अधिकारियों के बीच मुकाबला

भोपाल । मध्यप्रदेश पुलिस में वर्ष 2026 के अंत तक बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना का एक वर्ष का सेवा विस्तार 1 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। यदि राज्य सरकार उन्हें दोबारा विस्तार नहीं देती है तो प्रदेश को नया पुलिस प्रमुख मिलेगा। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय से लेकर सत्ता के गलियारों तक नए डीजीपी के नामों पर मंथन शुरू हो रहा है। वरिष्ठता, सेवा अवधि और अनुभव को देखते हुए डीजी ईओडब्ल्यू उपेंद्र जैन, डीजी जेल वरुण कपूर और स्पेशल डीजी (सीआईडी) पंकज श्रीवास्तव को डीजीपी पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। इनमें वरिष्ठता और न्यूनतम कार्यकाल की उपलब्धता के कारण उपेंद्र जैन का नाम सबसे मजबूत बताया जा रहा है। डीजीपी कैलाश मकवाना का नियमित कार्यकाल 1 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया था। हालांकि सरकार चाहे तो उन्हें एक और वर्ष का विस्तार दे सकती है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में इसकी संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। ऐसे में दिसंबर के बाद नए डीजीपी की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। डीजीपी पद के लिए जिन अधिकारियों के नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं, उनमें उपेंद्र जैन महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, वरुण कपूर महानिदेशक, जेल और पंकज श्रीवास्तव स्पेशल डीजी, सीआईडी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, यदि वरिष्ठता और कार्यकाल को प्राथमिकता दी जाती है तो उपेंद्र जैन सबसे आगे रह सकते हैं।

2027 में एक साथ रिटायर होंगे 13 आईपीएस अधिकारी

अगले वर्ष प्रदेश पुलिस महकमे में सेवानिवृत्ति का बड़ा दौर आने वाला है। वर्ष 2027 में कुल 13 आईपीएस अधिकारी सेवा से निवृत्त होंगे। इनमें सात प्रमोटी और छह डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। जो अधिकारी सेवानिवृत्ति होंगे उनमें जनवरी में राकेश सगर, मार्च में मुकेश श्रीवास्तव, मई में वरुण कपूर, जून में ओमप्रकाश त्रिपाठी, विनोद कुमार सिंह, संतोष सिंह गौर, जुलाई में जी. अखेतो सेमा, राजाबाबू सिंह, अगस्त में उपेंद्र जैन, अक्टूबर में उमेश जोगा, मनोज कुमार सिंह, रसना ठाकुर, दिसंबर में पंकज श्रीवास्तव शामिल हैं। इसी वजह से डीजीपी चयन में अधिकारियों के शेष सेवा काल को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस साल भी 16 आईपीएस हो रहे हैं सेवानिवृत्त

वर्ष 2026 में भी आईपीएस कैडर में बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्तियां हो रही हैं। कुल 16 अधिकारियों को इस वर्ष रिटायर होना है। अब तक जिन अधिकारियों की विदाई हो चुकी है, उनमें जगदीश डाबर, अंशुमान सिंह, हिमानी खन्ना, सविता सोहाने, जितेंद्र सिंह पंवार, महेशचंद्र जैन, संजीव शमी, आलोक रंजन और संजय तिवारी शामिल हैं।

जुलाई और अगस्त में कई वरिष्ठ अफसर होंगे विदा

इसी माह अरविंद सक्सेना और शशिकांत शुक्ला भी सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद अगस्त में सबसे अधिक चार वरिष्ठ अधिकारी अजय शर्मा, आशुतोष रॉय, ए. साई मनोहर और मिथिलेश शुक्ला सेवानिवृत्त होंगे। वहीं अक्टूबर में वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में प्रतिनियुक्ति पर महानिदेशक के रूप में कार्यरत सोनाली मिश्रा भी सेवा से निवृत्त होंगी। लगातार हो रही सेवानिवृत्तियों के कारण आने वाले महीनों में पुलिस मुख्यालय, जोन, रेंज और जिला स्तर पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नए डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी व्यापक बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए नई तबादला सूची जारी होने की भी संभावना है।

पीडब्ल्यूडी में इंटरनल ऑडिट से करप्शन पकड़ेंगे

चीफ इंजीनियर की टीम करेगी डिवीजन ऑफिस की जांच, भुगतान और निर्माण क्वालिटी पर फोकस

भोपाल । प्रदेश भर में लोक निर्माण विभाग के सभी संभागीय कार्यालयों में इंटरनल ऑडिट होगी। इसके जरिए विभाग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन की स्थिति लाना चाहता है। ऑडिट के दौरान निर्माण कार्य स्वीकृति से लेकर भुगतान और परफॉर्मेंस गारंटी तक सभी प्रमुख बिंदुओं की जांच की जाएगी। इससे सडक़ निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि कार्यों की तकनीकी और वित्तीय जांच होगी। सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जिससे जनता के टैक्स का सही उपयोग होगा।

इंटरनल ऑडिट में यह देखा जाएगा कि टेंडर प्रक्रिया तय नियमों एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप हुई या नहीं हुई। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी होने के बाद समय-सीमा में अनुबंध किया गया या नहीं किया गया। साथ ही बिलों का भुगतान शासन के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस सिद्धांत के अनुसार हुआ है या अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की नीति अपनाई गई है। इसके अलावा अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप हुआ या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। विभाग ने ऑडिट के दौरान भुगतान से पहले पोर्टल पर आवश्यक वेरिफिकेशन की जांच करने के लिए भी कहा है।

निरीक्षण टीम करेगी मौके पर जांच

निर्देशों में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता स्तर पर निरीक्षण दल गठित किए जाएंगे। ये दल संभागीय कार्यालयों का निरीक्षण कर रिकॉर्ड एवं निर्माण कार्यों की जांच करेंगे। निरीक्षण के बाद प्रतिवेदन विभाग को सौंपा जाएगा तथा आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग का मानना है कि परफॉर्मेंस गारंटी और आईआरआई परीक्षण की जांच से सडक़ों की गुणवत्ता पर निगरानी मजबूत होगी, जिससे नागरिकों को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित सडक़ें मिल सकती हैं। समय-वृद्धि और अतिरिक्त कार्यों की समीक्षा से अनावश्यक लागत बढऩे पर नियंत्रण रहेगा।

कार्टून कोना....

मध्यप्रदेश में बिजली संकट का एआई से निकलेगा समाधान...

24 घंटे होगी ग्रिड की स्मार्ट निगरानी, थमेगी अघोषित कटौती

भोपाल । प्रदेश में तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग के बीच बिजली कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ग्रिड संचालन को स्मार्ट बनाने की तैयारी में हैं। इस तकनीक के जरिए बिजली की मांग का पहले से अनुमान लगाया जाएगा।

इससे समय पर ग्रिड का बेहतर प्रबंधन और तकनीकी खराबियों की समय रहते पहचान संभव होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना और अघोषित कटौती की स्थिति को कम करना है।

प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान अधिकतम बिजली मांग 14,089 मेगावाट थी, जो वर्ष 2024 में बढक़र 18,913 मेगावाट तक पहुंच गई। वर्तमान में यह आंकड़ा करीब 20 हजार मेगावाट के आसपास है। ऊर्जा क्षेत्र के अनुमान के अनुसार वर्ष 2027-28 तक अधिकतम मांग 22 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है। बढ़ती जरूरत को देखते हुए बिजली कंपनियां पारंपरिक व्यवस्था के बजाय डिजिटल तकनीकों पर फोकस कर रही हैं।

ग्रिड पर रहेगी पैनी नजर

और एससीएडीए प्रणाली का उपयोग

एआई से लैस एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) प्रणाली नियंत्रण केंद्रों को ग्रिड की वास्तविक स्थिति का लगातार आकलन करने में मदद करेगी। इसके जरिए वोल्टेज नियंत्रण, मांग-आपूर्ति संतुलन, आर्थिक डिस्पैच और पीक लोड प्रबंधन जैसे निर्णय अधिक तेजी और सटीकता से लिए जा सकेंगे। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढऩे की उम्मीद है।

ट्रांसमिशन लाइनों की निगरानी होगी स्मार्ट और ड्रोन का इस्तेमाल

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा भी ड्रोन आधारित निरीक्षण व्यवस्था को और उन्नत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। द्ध आधारित इमेज एनालिसिस तकनीक की मदद से ट्रांसमिशन लाइनों, टावरों और उपकरणों में संभावित खराबियों की समय रहते पहचान की जा सकेगी। इससे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक ट्रिपिंग की घटनाओं में कमी आएगी।

हरित ऊर्जा के लिए भी उपयोगी होगी यह आधुनिक तकनीक

प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। इन स्रोतों का उत्पादन मौसम पर निर्भर होने के कारण इनमें उतार-चढ़ाव बना रहता है।। द्ध आधारित विश्लेषण प्रणाली मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का बेहतर पूर्वानुमान तैयार कर सकेगी, जिससे ग्रिड संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

एआई से होंगे ये फायदे

मांग बढऩे का पहले से मिलेगा अनुमान

ग्रिड की 24 घंटे स्मार्ट निगरानी

ड्रोन से ट्रांसमिशन लाइनों की जांच, खराबी आने से पहले होगी मरम्मत,

ट्रिपिंग और तकनीकी फाल्ट में आएगी कमी

सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन

-आंकड़ों में बढ़ती बिजली मांग

वर्ष अधिकतम मांग

2018-19 14,089 मेगावाट

2024 18,913 मेगावाट

वर्तमान करीब 20,000 मेगावाट

स्वामी मेसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम.पी.) प्रा.लि. इंदौर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मोनिका सेठ द्वारा 17, न्यू देवास रोड (संजय गांधी मार्ग) इंदौर से मुद्रित एवं 5, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित संपादक-मोनिका सेठ,
फोन नं. 3551753, 2434701, 2544433, समाचार पत्र से प्रकाशित समाचार के लिए सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा। समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार*